भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2565

16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

ईवी को बढ़ावा देना और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना

2565. **डॉ. आनन्द कुमार गोंडः**

श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को कोई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) अब तक कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरी बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें लागू की हैं:-

(i) भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया) स्कीम: फ़ेम इंडिया स्कीम का द्वितीय चरण 5 वर्ष की अवधि यानी 01.04.2019 से 31.03.2024 तक 11,500 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ लागू किया गया था।

(ii) भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग (पीएलआई-ऑटो) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम: सरकार ने इस स्कीम को 23.09.2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु मंजूरी दी थी। यह स्कीम न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ

ईवी सहित एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य शृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(iii) **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम संबंधी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** सरकार ने 12.05.2021 को 18,100 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी थी। इस स्कीम का लक्ष्य 50 गीगावॉटघंटा एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** यह स्कीम 10,900 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 01.04.2024 से 31.03.2028 तक लागू की गई है। इस स्कीम का लक्ष्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देना है। इस स्कीम में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए भी समर्थन शामिल है। इस स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय खरीदारों (उपभोक्ताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को ई-दुपहिया, ई-तिपहिया (ई-रिक्शा और ई-कार्ट), ई-तिपहिया (एल5), ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस पर कीमत में अग्रिम छूट के रूप में मांग प्रोत्साहन दिया जाता है।

(v) **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम:** 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रूपए है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा चूक करने की स्थिति में ई-बस संचालको को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई):** यह स्कीम 15.03.2024 को भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित की गई थी।

(ग), (ङ) और (च): इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि है और निजी उद्यमी भी इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों सहित ईवी चार्जिंग को मजबूत करने के लिए 17.09.2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए। ये दिशानिर्देश बैटरी-स्वैपिंग स्टेशनों को शामिल करके एक कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल चार्जिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं।
इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है।

(घ): बीएचईएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक कुल 29,151 ईवी चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए जा चुके हैं।

****